जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 63 प्रभात चूरू, सोमवार 30 जून, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

देश के सबसे पुराने स्पोर्ट्स क्लब के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों : यातनाएं ही यातनाएं

जयपुर के यूनियन फुटबाल ग्राउण्ड को लुटेरे ही लुटेरे क्यों मिले, रखवाले क्यों नहीं?

यूनियन ग्राउण्ड के इस फोटो में देखा जा सकता है कि जेडीए ने अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग से बाहर आने के लिए बनाये गये चार निकास द्वारों को ग्राउण्ड की जमीन में ही खोल दिया है, जिससे ग्राउण्ड का क्षेत्रफल कम हो गया है। फोटो में ये निकास द्वार ग्राउण्ड के बाईं तरफ की सीमा पर गुलाबी रंग के कमरे नुमा ढांचों के रूप में नज़र आ रहे हैं।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 29 जून। रामनिवास बाग और जयपुर हैरिटेज को सुरक्षित रखने तथा देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब को सुदृढ़ करने के बजाय अफसरशाही इसे उजाडने पर तुली है। क्योंकि रामनिवास बाग में वर्ष 1889 में बने यूनियन फुटबॉल क्लब से जो भूमि, जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूमिगत पार्किंग विकसित करने के लिए ली थी, अब वहां उजड़ा हुआ खाली मैदान यूनियन क्लब को लौटाया जा रहा है। इसकी हालत ऐसी है कि ना तो खिलाड़ी फुटबॉल खेल सकते हैं और ना ही यहां कोई मैच आयोजित कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भूमिगत पार्किंग बनाने के प्रस्ताव से पहले भी जे.डी.ए. और राज्य सरकार ने फुटबॉल ग्राउंड से जमीन ली, ताकि वह न्यू गेट से अल्बर्ट हॉल की ओर आवाजाही के लिए अस्थायी सड़क मार्ग विकसित कर सके। जब तक कि रविन्द्र मंच के सामने से महाराजा सवाई मानसिंह की मूर्ति तक जा रही सड़क को विकसित कर लें। हालांकि यह मार्ग विकसित होने के बाद भी यह जमीन यूनियन फुटबॉल क्लब को नहीं लौटाई है।

ज्ञात रहे कि वर्ष 2019 में तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जेडीए कमिश्नर और स्मार्ट सिटी सीईओ भी शामिल थे। इन्होंने जयपुर शहर के एम.आई. रोड तथा परकोटे के किशनपोल बाजार, चौड़ा रास्ता और जौहरी बाजार व इसके आसपास के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के वाहन पार्किंग का प्रस्ताव रामनिवास बाग के लिए तैयार किया। यहां मौजूदा 915 कारों की मौजूदा पार्किंग पूर्ण भराव क्षमता के साथ होने के कारण यूनियन फुटबॉल क्लब की जमीन के नीच नई भूमिगत पार्किंग विकसित करने की मंजूरी दी गई। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद जेडीए प्रशासन ने यूनियन फुटबॉल क्लब के सचिव को पत्र लिखकर उनसे फुटबॉल ग्रांउड की जमीन मांगी। साथ ही यह वादा भी किया कि ग्राउंड के नीचे भूमिगत पार्किंग विकसित किए जाने के बाद जे.डी.ए. प्रशासन यहां पर पुनः फुटबॉल ग्राउंड विकसित करके क्लब को सौंपेगा। जब तक भूमिगत पार्किंग का प्रोजेक्ट का कार्य चलेगा, तब तक रामनिवास बाग स्थित जयपुर क्रिकेट क्लब (जे.सी.सी.) ग्राउंड की जमीन?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूनियन क्लब ग्राउण्ड का पूर्वी गेट इस तस्वीर में देखा जा सकता है। गेट के सामने बनी सड़क यूनियन ग्राउण्ड को आवंटित भूमि पर बनी है। प्रशासन व राज्य सरकार ने यूनियन क्लब से तब तक के लिए उक्त भूमि पर अस्थाई सड़क के निर्माण के लिए अनुमति ली थी जब तक रविन्द्र मंच के सामने बन रही सड़क का कार्य पूरा नहीं हो जाता। परन्तु जिस भूमि पर अस्थाई सड़क बनी है उसे यूनियन क्लब को नहीं लौटाया गया। इसी सड़क से जुड़ी सी-सी रोड, जो सवाई मानसिंह जी की मूर्ति तक जाती है, वह भी यूनियन क्लब की जमीन पर बनी हुई है, जिसे भी यूनियन क्लब को नहीं लौटाया गया।

- **भूमिगत पार्किंग के चक्कर में, वर्ष 1889 में बने यूनियन फुटबॉल क्लब के ग्राउण्ड को भी उजाड़ा।**
- **राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग स्थित फुटबॉल ग्राउण्ड के नीचे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बनाया था पार्किंग का प्रस्ताव।**
- **क्लब के सचिव का आरोप है कि जे.डी.ए. ने मनमुताबिक नक्शे बदले और पार्किंग के निकासी द्वारा भी क्लब की जमीन में बना डाले।**
- **फुटबॉल ग्राउण्ड की दशा इतनी उजड़ी हुई है कि यहां फुटबॉल खेलना तो दूर कोई अन्य सामान्य खेल भी नहीं खेला जा सकता है।**

प्रशासन ने यूनियन क्लब के ग्राउण्ड के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग बनाने के प्रस्ताव में यह स्पष्ट लिखा था कि ग्राउण्ड को लौटाते समय वह उसे हरा भरा बना कर देंगे ओर ग्राउण्ड की जमीन पर कोई नया निर्माण नहीं होगा। परन्तु इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ग्राउण्ड के दक्षिण की तरफ, जहां माधोसिंह द्वितीय के कार्यकाल के दौरान बने सिंचाई के टैंक और टीन का छज्जा है, वहीं पर जेडीए प्रशासन ने अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग से जुड़ा एफ ''वैन्ट'' बनाया है। इस वैन्ट पर गुलाबी रंग का 10 गुणा 10 का कमरा नुमा ढांचा बनाया हुआ है और इसका एक काले रंग का गेट है।

कर्नाटक में फिर चलने लगी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा

विधायक ने दावा किया कि 2-3 माह में डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं

बंगलूरू, 29 जून। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को लेकर विधायक हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका दावा है कि शिवकुमार को अगले दो से तीन महीनों में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

- **दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतीन्द्र ने नेतृत्व परिवर्तन की बातों को अफवाह करार दिया।**

कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन शिवकुमार के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनके दावे को लेकर सियासत और तेज है। उन्होंने कहा कि जो नेता कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे थे, अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हुसैन ने कहा, "सबको पता है कि हमारी सरकार किसकी मेहनत से बनी। शिवकुमार की रणनीति और काम को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।

विधायक हुसैन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने हाल ही में सितंबर के बाद बड़ी सियासी हलचल की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद ही फिर से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र ने इस तरह की बातों को अफवाह करार दिया है।

इकबाल हुसैन ने साफ कहा कि कांग्रेस में अंतिम फैसला हाईकमान ही करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में सरकार बनाने का फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र में तीन भाषा नीति लागू नहीं होगी

मुंबई, 29 जून। महाराष्ट्र सरकार की तीन भाषाओं को लागू करने की नीति रद्द हो गई है। राज्य सरकार को इस नीति की वजह से पिछले कुछ दिनों से शिक्षाविदों, राजनीतिक दलों और

- **बड़े विरोध के कारण महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय बदला। तीन भाषा नीति में, राज्य के स्कूलों में हिन्दी को डिफॉल्ट तीसरी भाषा बनाने का फैसला हुआ था।**

नागरिक समाज समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को डिफॉल्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रथ यात्रा में भगदड़ : पुरी में 3 की मौत, 50 घायल

रविवार सुबह 4 बजे श्रीगुंडिचा मंदिर के पास दर्शनार्थियों की भीड़ अनियंत्रित हो गई

भुवनेश्वर, 29 जून। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे, जब भक्त श्रीगुंडिचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जमा हुए, उस दौरान वहां काफी धक्का-मुक्की हुई, कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुई है।जब सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर के पास एकत्र हुए थे। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने कहा कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 6 लोगों की हालत गंभीर है।

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच चल रही है।

- **पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। रथ यात्रा के दौरान भगवान को श्री मंदिर से बाहर श्रीगुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इस यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ।**
- **ओडिशा सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जाँच के आदेश दिये। कलक्टर, एसपी का ट्राँसफर किया व दो पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया।**

घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस हादसे पर माफी मांगते हुए एक बयान जारी किया और घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए हैं। माझी ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विकास आयुक्त की देखरेख में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच का गठन किया गया है। हादसे के बाद पुरी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से पुरी से हटा दिया गया है। दो पुलिस अधिकारियों पुलिस उपायुक्त बिष्णु पति और कमांडेंट अजय पाधी को भीड़ को प्रभावी ढ ंग से नियंत्रित करने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया।

राज्य सरकार ने भगदड़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने में सरकार की घोर विफलता के लिए भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की।

चार धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित

देहरादून, 29 जून। उत्तराखंड में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है।

गढ़ वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने रविवार को बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

- **गढ़वाल मंडल आयुक्त के अनुसार, आगे की यात्रा का निर्णय मौसम व मार्गों की समीक्षा के बाद किया जायेगा।**

उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति सोमवार को दो दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुँचेगी

गोरखपुर, 29 जून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन और उनके दो दिवसीय कार्यक्रमों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में गोरखपुर इतिहास रचने को तैयार है। इन दो दिनों में राष्ट्रपति न केवल तीन बड़े संस्थानों केमहत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी बल्कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 129 किलोमीटर की दूरी सड़क

- **वे गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पदक देंगी।**

मार्ग से तय करेंगी।

राष्ट्रपति सोमवार (30 जून) को दोपहर में गोरखपुर आएंगी और अगले दिन मंगलवार (01 जुलाई) की शाम प्रस्थान करेंगी। वे यहां 30 घंटे रहेंगी और उनके सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों तक सड़क मार्ग से ही जाने की तैयारी है। सोमवार को वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मेधावियों को पदक प्रदान करेंगी और एक जुलाई को पूर्वाह्न राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जनगणना के पहले चरण में 1 अप्रेल 2026 से मकानों का सूचीकरण होगा

दूसरे चरण में 1 फरवरी 2027 से हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जानकारी ली जायेगी

नई दिल्ली, 29 जून। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2026 के पहले चरण की तारीख तय कर दी है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और हाउसिंग जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।

दो चरणों में जनगणना होगी। पहला चरण, मकान सूचीकरण काम, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) भी कहा जाता है, इसमें हर घर की स्थिति, सुविधाएं और संसाधनों की जानकारी ली जाती है। वहीं दूसरा चरण, जनसंख्या गणना का है, यह चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। इसमें हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जानकारी ली जाएगी।

इस चरण में सरकार यह पता लगाएगी कि घर की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री की बनी है। घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, घर में शादीशुदा जोड़े हैं या नहीं, क्या घर का मुखिया महिला है या वह अनुसूचित जाति/जनजाति से है।

- **जनगणना आयुक्त के अनुसार, इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। मोबाइल एप का उपयोग किया जायेगा।**

इस बार की जनगणना खास होगी क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। साथ ही, लोगों को स्वयं से जानकारी देने की सुविधा भी दी जाएगी।

सरकार ने बताया कि जनगणना के लिए 34 लाख से अधिक पर्यवेक्षक और गणनाकार तैनात किए जाएंगे। वहीं 1.3 लाख से अधिक जनगणना अधिकारी काम में लगाए जाएंगे। यह भारत की 16वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं बार जनगणना होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार जातिगत आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। यह फैसला लंबे समय से सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)